



डॉ० चन्द्रकेश कुमार

कोविड-19 : भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ

असि० प्रोफेसर- अर्थशास्त्र, बी०बी०डी० पी०जी० कॉलेज, परुड्य्या आश्रम,
अम्बेडकरनगर (उ०प्र०), भारत

Received- 03.12. 2021, Revised- 09.12. 2021, Accepted - 14.12.2021 E-mail: kchandrakesh98@gmail.com

साक्ष्यः वर्तमान समय में कोरोना वायरस का प्रकोप सबसे पहले 31 दिसम्बर 2019 को चीन के बुहान शहर से हुआ था। भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के बारे में विस्तार से पढ़ने से पहले कोरोना वायरस के बारे में जानते हैं कि कोरोना वायरस है क्या?

कोरोना वायरस महामारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को जबरदस्त झटका दिया है। इससे देश के आर्थिक विकास में भारी गिरावट आने वाली है। इस महामारी पर अंकुश के लिए सरकार ने देश व्यापी बन्दी लागू की है। इससे लोगों की आवाजाही वस्तु आपूर्ति प्रभावित हुई है, परन्तु हमारी सरकार को भी चाहिए कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भारत में भी प्रभावशाली अर्थशास्त्रीयों की एक कमेटी का गठन किया जाय जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष इस चुनौतियों को चरणबद्ध तरीके से कुशलता पूर्वक समाधान सरकार के समक्ष रखे। कोरोना वायरस (COV) वायरस का एक बड़ा परिवार है, जो बिमारी का कारण बनता है।

इसे सामान्य सर्दी से लेकर Middle East Respiratory Syndrome (MERS-COV) और Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-COV) जैसे गम्भीर बीमारियाँ हो सकती है। नावेल कोरोना वायरस, का एक नया प्रकार है जो अभी तक मानव में नहीं पाया गया था।

कुंजीभूत शब्द- कोरोना वायरस, भारतीय अर्थव्यवस्था, महामारी, आर्थिक विकास, प्रभावित, प्रभावशाली।

कोरोना महामारी कोविड-19 के मुख्य विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इन परिस्थितियों का कितना गहरा असर पड़ेगा, ये कुछ बातों पर निर्भर करेगा। एक तो ये कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस की समस्या भारत में कितनी गम्भीर होती है और दूसरा की कब तक इस पर काबू पाया जाता है

हम इस बात को नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं कि चीन और दुनिया के अन्य देशों में Covid-19 के प्रकोप से पुरे विश्व स्तर पर आर्थिक मंदी, व्यवसायिक चक्र की समस्या, बेरोजगारी, गरीबी, यातायात, विदेशी व्यापार, मांग-पूर्ति आदि प्रमुख चुनौतियाँ सामने उभरकर आ रही है। कोरोना वायरस ने न केवल भारत की बल्कि पुरे विश्व की अर्थव्यवस्था की हालत खराब कर रखी है। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के कारण, भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ने वाला है और कोरोना के वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि में भारी गिरावट आयेगी। आज तमाम विधानों का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस पारिस्थितियों का कितना गहरा असर पड़ेगा ये दो बातों पर निर्भर करेगा।

पहला भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे पिछड़ा क्षेत्र निर्धन क्षेत्र यानी मध्यवर्गीय परिवार, किसान, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, माल में काम करने करने वाले, दैनिक मजदूरी के लिए शहरों में पलायन करने वाले मजदूर सड़कों के किनारे छोटा-मोटा व्यापार करके आजीविका चलाने वाले लोगो की समस्या गम्भीर होगी।

दूसरा-भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन करने वाले, यानी वह क्षेत्र जो इस देश में पूंजी और गैर पूंजीगत वस्तुओं का उत्पाद करता है, सामान्य भाषा में कहे तो मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर या विजनेस सेक्टर।

देशभर की सरकारें इन दोनों पहलुओं पर काम कर रही है और अपने देश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए बड़ा राहत पैकेज की घोषणा किया और उसी क्रम में भारत सरकार ने भी गरीबों की मदद करने के लिए बड़े पैकेज का ऐलान किया है। सरकार ने पहले चरण में जो राहत पैकेज जारी किया है वह पूरी तरीके से कमजोर और असंगठित क्षेत्र के लोगों के समस्याओं के समाधान के लिए है। कोरोना वायरस के वजह से आये आर्थिक संकट से जूझ रहे, इस तपके के लिए सरकार ने 1.7 लाख करोड़ ₹ का पैकेज जारी किया है। वैश्विक स्तर पर देखा जाय तो अमेरिका ने सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज अपने अर्थ व्यवस्था के लिए जारी किया है। अमेरिका ने करीब 30 करोड़ लोगो के लिए 2 मिलियन डालर यानी कुल 151 लाख करोड़ ₹ का राहत पैकेज जारी किया है। यह भारत के कुल बजट का लगभग 5 गुना ज्यादा है, यह अमेरिका के पूरी अर्थव्यवस्था के लिए है।

अगर देखा जाय तो भारत सरकार ने मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए किसी बड़े पैकेज का ऐलान नहीं किया है। ऐसी उम्मीद है कि जल्द ही निकट भविष्य में भी किसी बड़े पैकेज का ऐलान किये जाने की सम्भावना है मांग के साथ- साथ अब वस्तु आपूर्ति आधारित संकट देखे जा रहे है, उत्पादन क्षेत्र को सूचारू रूप से दोबारा चालू करने के लिए एक बड़े आर्थिक पैकेज की जरूरत पड़ेगी। केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी हो रहे राहत पैकेज के बीच में दो प्रमुख बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

**1. भारत का एक तो मध्यवर्गीय परिवार 2. आने वाले विभिन्न आर्थिक संकट की जड़**

मध्यवर्गीय परिवार की परिचर्चा का प्रमुख बिन्दु बनाना इस लिए अति आवश्यक है क्योंकि अर्थव्यवस्था में जारी हर संकट के बीच मध्यवर्गीय परिवार कमजोर होता है। क्योंकि सरकारों द्वारा जारी होने वाला राहत पैकेज में यह परिवार शामिल नहीं हो पाता है। आर्थिक संकट की घड़ी में अक्सर मध्यवर्गीय परिवारों का एक हिस्सा, अर्थव्यवस्था में गरीब आबादी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। वर्तमान में Covid-19 का संकट भी कुछ ऐसे संकेत दे रहा है।

यह अक्सर छोटी सैलरी पर काम करने वाला मध्यवर्गीय परिवार इस संकट में अधिक कमजोर हो और लोवर मध्यवर्गीय परिवार या उससे नीचे की श्रेणी के तरफ शिफ्ट हो जाये। IMF ने अपने रिपोर्ट में इस तथ्य का जिक्र किया कि भारत का मध्य वर्गीय परिवार सिकुड़ रहा है। इसी लिए यह जरूरी हो जाता है कि संकट के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था में मौजूद मध्य वर्गीय परिवार की भी आर्थिक परिस्थितियों को भी प्रमुखता से ध्यान दिया जाय।

अब दूसरा प्रमुख मुद्दा आर्थिक संकट के जड़ को सुनने का है। प्रश्न यह उठता है कि कोविड-19 की वजह से जारी आर्थिक संकट की मूल बिन्दु (जड़) या उसके निवारण का केन्द्र बिन्दु क्या होना चाहिए? क्या कोविड-19 को ही भारतीय अर्थव्यवस्था की सुस्ती का कारण मानकर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की पूर जोर कोशिश करनी चाहिए या फिर पिछले दो साल से चली आ रही आर्थिक सुस्ती को भी जड़ (बुनियाद) के रूप में लेते हुए किसी नये प्लान पर विचार करना चाहिए।

अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से तो यही सही होगा कि जारी आर्थिक संकट से निपटने के लिए इसकी जड़ को ईमानदारी से चुना जाय, वर्तमान जारी आर्थिक संकट से पहले ही भारत में एक बड़ी मांग आधारित आर्थिक सुस्ती आ चुकी थी और यह मांग के साथ-साथ आपूर्ति आधारित सुस्ती का रूप धारण कर चुकी है।

कोविड-19 महामारी आने के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था नामिनल ळक् के आधार पर 45 साल के न्यूनतम स्तर पर थी रियल GDP के आधार पर 11 साल के न्यूनतम स्तर पर थी बेरोजगारी की दर पूर्व के 45 सालों में सबसे अधिक थी और ग्रामीण मांग पिछले 40 साल के न्यूनतम स्तर पर थी इसीलिए बेहतर यह होगा कि जारी आर्थिक संकट को भी संज्ञान में लिया जाय। तब जाकर कही कोविड-19 महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को दोबारा तेजी से आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत रणनीति का निर्माण हो सकता है। वर्तमान समय की बात करें तो कोरोना वायरस के प्रकोप ने भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ कर रख दी है। विभिन्न प्रमुख राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर के सम्बन्ध में जो आकड़े जारी किये हैं, वे असंतोष जनक हैं।

IMF, World Bank, ADB मूडीज जैसी संस्थाओं ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान जारी कि है।

IMF के अनुसार भारत की GDP विकास दर 1.9 फीसदी रह सकती है, World Bank ने सम्भावनाएं जतायी है, पहली सम्भावना यह कि अगर भारत सही वक्त पर सही तरिके से कन्ट्रोल करने में सफल रहा तो अर्थव्यवस्था में GDP वृद्धि दर 4 फीसदी रहेगी अगर संकट गहराता है और लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाता है तो यह वृद्धि दर घटकर 1.5 फीसदी हो जायेगी। ADB (एशियन डेवेलोपमेन्ट बैंक) के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2020-21 में 4 फीसदी सम्भावित है, मूडिज के अनुसार भारत की GDP दर का अनुमान वर्ष 2020-21 के लिए 2.5 फीसदी है।

UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार जिस गति से कोविड से विकासशील देशों को झटका लगा है, वह काफी ड्रामेटिक है UNCTAD के महासचिव मुखिसा (Mukhisa) ने कहा "सदमे से आर्थिक गिरावट जारी है और भविष्यवाणी करना मुश्किल है, लेकिन स्पष्ट संकेत है कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए चीजे बहुत खराब होगी।" जब की RBI ने मनेटरी पॉलिसी कमेटी की फरवरी के बैठक में वर्ष 2020-21 के लिए 6 फीसदी GDP विकास दर का अनुमान लगाया था।

इन सभी समस्याओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था 'रिवर्स माइग्रेशन' को भी देख रही है, अभी यह देश के भीतर ही हो रहा है। अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी यह बड़े स्तर पर सम्भव है। उदाहरण के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका में 'इमीग्रेशन' रोकने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

अब आने वाले कुछ दिनों तक अमेरिका में किसी बाहरी व्यक्ति को रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं होंगे। यानी लड़ाई संकट के बीच खत्म हो रही नौकरियों को देखते हुए लिया गया है। जहाँ अमेरिकी सरकार अब इनकी जगह स्थानीय लोगों को रोजगार देगी।

इस संकट ने अमेरिकी में भी बेरोजगारी को उच्चतम स्तर पर पहुँचा दिया है। अमेरिका में मार्च महीने के अन्त तक कुल 66 लाख से ज्यादा कामगारों ने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन कर दिया था। यह अमेरिका के इतिहास में अब तक बेरोजगारी भत्तों के लिए आवेदन करने वालों की सबसे बड़ी संख्या थी। वही अगर भारत के सन्दर्भ में बात करें तो 'सेन्टर फॉर मानिट्रिंग



इंडियन इकोनोमी' (सी0एम0आई0ई0) के जारी आकड़ों के अनुसार, लॉकडाउन की वजह से कुल 12 करोड़ नौकरियां चली गयी है। कोरोना महामारी से पहले भारत में कुल रोजगार आबादी की संख्या 40.4 करोड़ थी, जो इस संकट के बाद घटकर 28.5 करोड़ हो चुकी है।

फिलहाल WHO की माने तो कोविड-19 के संकट का अभी सबसे बुरा वक्त आना बाकी है यौनी कि आज यह निष्कर्ष निकालना कठिन है कि अर्थव्यवस्था का सबसे बुरा वक्त क्या होना वाला है? हम सभी सिर्फ सम्भावनाएं जता सकते हैं, लेकिन जरूर स्पष्ट होता जा रहा है कि अर्थव्यवस्था में मांग एवं आपूर्ति आधारित सुस्ती के साथ-साथ गरीबी, बेरोजगारी का भीषण संकट आ रहा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शब्दों में कहे तो हमे जान और जहान दोनों बचाना है, लेकिन साथ-साथ अपने लोगों की जीविका को बचाने के लिए आर्थिक मोर्चे पर कुछ बड़े फेसले लेने होंगे। जारी कोरोना हेल्थ इमरजेंसी के बाद एक बड़ी इकोनॉमी इमरजेंसी आने वाली है, जो इस संकट से ज्यादा भयावह और कही अधिक जाने ले सकती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. कोरोना वायरस के कारण भारत में पैदा हुई आर्थिक चुनौतिया (ORF) मूल से 10 मई 2020 को पुरालेखित अभिगमन तिथि 25 जुलाई 2020.
2. कोरोना वायरस ने की भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट-12.04.2020 TI01%37%50%173.
3. कोविड-19 भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस का क्या प्रभाव होगा? अप्रैल 01.04.2020.
4. G.D.P विकास अनुमान, भारतीय अर्थव्यवस्था को कोरोना से पहुंचेगी गहरी चोट नई दिल्ली 23 अप्रैल 2020.
5. कोरोना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए झटका 2020-21 में वृद्धि दर घट कर 2.8% रहेगी विश्व बैंक बिजनेस डेक्स नई दिल्ली 12 अप्रैल 2020 11%-38.
6. कोरोना इंपैक्ट: 1991 के बाद सबसे खराब रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन FY21 में 1.5-2.8% के बीच रहेगी ग्रोथ रेट PTI Aril 12.04.2020 04.014 PM
7. कोरोना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका 2020-21 में वृद्धि दर घटकर 2.8% रहेगी- World Bank AVP News 12.04-2020:21:10PM
8. कोरोना संकट के बीच क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतिया ET Contributors April 26.04.2020:09:30IST
9. सभी नेट से।
